

RNI No. RAJHIN/2007/26996
ISSN 0976-7452 Raaso
Refreed Journal

रासो

अन्तर्विषयी त्रैमासिक शोध पत्रिका

वर्ष-16, अंक-4, सितम्बर अक्टूबर नवम्बर 2023





RNI No. RAJHIN/2007/26996
ISSN 0976-7452Raaso
Refreed Journal

रासो

इतिहास, संस्कृति, साहित्य एवं दर्शन की त्रैमासिक शोध पत्रिका

वर्ष-16

अंक - 4

सितम्बर-अक्टूबर-नवम्बर-2023

सम्पादक

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

निदेशक

कॉम्पिटिशन प्लस संस्थान, ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, अजमेर (राजस्थान)

संरक्षक

* प्रो. जे. पी. शर्मा - पूर्व कुलपति, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

सलाहकार मण्डल

- * प्रो. विभा उपाध्याय - प्रोफेसर, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)
- * नर्मदा प्रसाद उपाध्याय - प्रसिद्ध साहित्यकार तथा संस्कृति चिंतक, इन्दौर (मध्य प्रदेश)
- * प्रो. टी.के. माथुर - पूर्व अध्यक्ष, इतिहास विभाग महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.)
- * डॉ. रमेश अग्रवाल - पूर्व स्थानीय सम्पादक, दैनिक भास्कर, अजमेर (राजस्थान)
- * डॉ. गौरव बिस्सा - सहआचार्य, विभागाध्यक्ष, प्रबंध अध्ययन विभाग, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
- * डॉ. बीना शर्मा - पूर्व विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर
- * प्रो. शोभा आर. मिश्रा - आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, माधव महाविद्यालय, उज्जैन
- * डॉ. वेद प्रकाश विद्यार्थी - पूर्व सहायक निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली।

☆ उप सम्पादक

डॉ. रीता पारीक

प्राचार्य

हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

☆ प्रबन्ध सम्पादक

डॉ. मृत्युंजय शर्मा

सह-आचार्य

हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

☆ सहायक सम्पादक

डॉ. निष्काम शर्मा

☆ शब्द संयोजन

मुकेश कुमार माहेश्वरी

☆ सम्पादकीय/सचिव

व्यवस्थापकीय कार्यालय

सृजन संस्थान,

आचमन, वेद विहार,

लोहाखान, अजमेर-06

दूरभाष : 0145-2426610

e-mail : rasoajmjournal@gmail.com

☆ प्रकाशक :

पुष्पा शर्मा

सृजन संस्थान,

द्वारा आचमन पब्लिकेशन्स,

अजमेर

☆ मुद्रक :

मैसर्स आर्य प्रिन्टर्स,

केसरगंज, अजमेर

☆ कम्प्यूटराइज्ड सेटिंग :

श्रीनिवास प्रिन्टोग्राफिक्स

132, पंचवटी कॉलोनी,

अजमेर दूरभाष : 0145-2442701

सहयोग दर

* वार्षिक सदस्यता - 500 रु. (चार अंक)

संस्थाओं हेतु - 600 रु. (चार अंक)

कृपया बैंक/ड्राफ्ट/मनीऑर्डर श्रीमती पुष्पा शर्मा, प्रकाशक, आचमन पब्लिकेशन्स,
अजमेर- 305006 के नाम भेजें।

प्रकाशक-श्रीमती पुष्पा शर्मा, 51/1509, वेद विहार, लोहाखान, अजमेर द्वारा मैसर्स सृजन संस्थान, अजमेर
की ओर से प्रकाशित एवं मुद्रक-श्रीमती उषा गर्ग द्वारा मैसर्स आर्य प्रिन्टर्स, केसरगंज, अजमेर से मुद्रित।

नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परम्परा का समावेश एवं महत्त्व

डॉ. सुनीता जांगिड़

सहायक आचार्य (शिक्षा विभाग)

हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परम्परा को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के युवा अपनी संस्कृति, परम्पराओं और नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन न होकर जीवन जीने की सही दिशा दिखाने वाली हो, यही इस नीति का लक्ष्य है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेक भाषाएँ, बोलियाँ, लोक कलाएँ, शास्त्रीय संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक परम्पराएँ मौजूद हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से इन सभी को आगे बढ़ाने और संरक्षित करने का प्रयास किया गया है।

भारतीय ज्ञान परम्परा केवल पुराने समय की बात नहीं है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। इसमें पढ़ाई-लिखाई, सोच-विचार, व्यवहार और जीवन-दर्शन सभी शामिल हैं। यह व्यक्ति को अपने बारे में जानने और अपनी पहचान समझने में मदद करती है। पारंपरिक ज्ञान हमारे समाज की बौद्धिक धरोहर है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह हमारी संस्कृति, रीति-रिवाज, विश्वास और जीवन-पद्धति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाती है।

नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परम्परा को शामिल करने से शिक्षा में आधुनिक विषयों के साथ-साथ अच्छे संस्कार, सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का भी विकास होगा। भारतीय ज्ञान परम्परा में कला, संस्कृति, दर्शन, समाज, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और प्रबंधन जैसे अनेक क्षेत्रों का ज्ञान मिलता है। इससे छात्रों को जीवन को समझने का एक व्यापक और संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त होगा।

भारतीय ज्ञान परम्परा को शिक्षा से जोड़ने पर भारत अपनी पुरानी गौरवशाली परम्पराओं को फिर से जीवित कर सकता है। इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा और विश्व को मार्गदर्शन देने वाला देश बन सकेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी संस्कृति और परम्पराओं को सुरक्षित रखना इसी का उद्देश्य है। यह परम्परा और आधुनिकता के बीच एक मजबूत संबंध बनाती है।

नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्कूलों और कॉलेजों में ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया है, जिसमें भारतीय ज्ञान परम्परा को विशेष स्थान मिले। इसी कारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है, ताकि प्री-स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक हर बच्चे को शिक्षा मिल सके।

नवीन शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्य :

भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना और देश की भाषाई विविधता को सुरक्षित रखना है। भारत में अनेक भाषाएँ और बोलियाँ प्रचलित हैं, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान का शोध-पत्र में उल्लिखित सन्दर्भ एवं विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी है, सम्पादक नहीं।

महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से इन भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाकर छात्रों की भाषा-दक्षता को प्राथमिकता दी गई है। इससे छात्र अपनी मातृभाषा और स्थानीय भाषा में सीख पाते हैं, जिससे वे अपनी संस्कृति और विरासत के प्रति गहरी समझ और सम्मान विकसित कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से ही संस्कृति जीवित रहती है, इसलिए भारतीय ज्ञान प्रणाली भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल देती है।

भारतीय ज्ञान परम्परा केवल बाहरी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के आंतरिक जीवन से भी जुड़ी हुई है। यह व्यक्ति को आत्मिक शांति प्रदान करती है और मन की भावनाओं को संतुलित रखना सिखाती है। योग, ध्यान, नैतिक आचरण और जीवन मूल्यों के माध्यम से भारतीय ज्ञान परम्परा मनुष्य को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। इस परम्परा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास भी है।

भारतीय ज्ञान परम्परा की जड़ें वैदिक काल से जुड़ी हुई हैं। वेदों, उपनिषदों, बौद्ध और जैन दर्शन में शिक्षा को जीवन का आधार माना गया है। प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला तथा वल्लभी जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। इन शिक्षण संस्थानों में दर्शन, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, राजनीति, व्याकरण और कला जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। किंतु पिछले लगभग 200-300 वर्षों में विदेशी शासन और आधुनिक शिक्षा पद्धतियों के प्रभाव के कारण भारतीय ज्ञान परम्परा धीरे-धीरे उपेक्षित होती चली गई, जिससे इसका निरंतर ह्रास होता गया।

इसी कारण नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परम्परा के अध्ययन-अध्यापन, लेखन और पठन-पाठन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में कला, संस्कृति, दर्शन, समाजशास्त्र, विज्ञान और प्रबंधन जैसे विषयों को भारतीय दृष्टिकोण से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे छात्रों को ज्ञान का एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण प्राप्त होता है, जो केवल पुस्तकीय न होकर जीवन से जुड़ा होता है।

भारतीय ज्ञान परम्परा को शिक्षा में शामिल करने से समाज और जीवन के मूल तत्व मजबूत होते हैं। छात्र अपनी परम्परागत ज्ञान प्रणाली को समझ पाते हैं और उसका उपयोग आधुनिक संदर्भों में करना सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। साथ ही भारतीय ज्ञान परम्परा आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के साथ जुड़कर नवाचार और अनुसंधान को भी बढ़ावा देती है।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को केवल रोजगार तक सीमित न रखकर जीवनोपयोगी बनाना है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देकर छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। शिक्षा को स्थानीय आवश्यकताओं और वैश्विक चुनौतियों से जोड़कर एक मजबूत और समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार भारतीय ज्ञान परम्परा और आधुनिक शिक्षा का समन्वय भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखता है।

शिक्षकों के कौशल उन्नयन की पहल एवं नई शिक्षा नीति 2025 का दृष्टिकोण

नई शिक्षा नीति 2025 में शिक्षकों के कौशल उन्नयन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शिक्षक ही शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। इस नीति का प्रमुख लक्ष्य यह है कि वर्ष 2025 तक लगभग 80

प्रतिशत शिक्षकों को नवीन शैक्षणिक तरीकों, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और डिजिटल उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाए। इससे शिक्षक समय के अनुरूप स्वयं को अद्यतन कर सकेंगे और छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से शिक्षा प्रदान कर पाएंगे।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 की नई शैक्षणिक संरचना के अनुरूप राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को बाल-केंद्रित शिक्षण, अनुभव आधारित शिक्षा और तकनीक आधारित पठन-पाठन की विधियों से परिचित कराया जाएगा। इसके साथ ही सतत व्यावसायिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी केंद्रित प्रशिक्षण मॉड्यूल को शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाया जा रहा है। इससे शिक्षक निरंतर सीखते रहेंगे और उनकी शिक्षण गुणवत्ता में सुधार होगा।

नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के बीच सहयोग और अनुभव साझा करने को भी प्रोत्साहित किया गया है। सहकर्मी-नेतृत्व वाली शिक्षण पहल के माध्यम से शिक्षक एक-दूसरे की सर्वोत्तम शिक्षण प्रथाओं को समझ सकेंगे और उन्हें अपने शिक्षण कार्य में लागू कर सकेंगे। इससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी, नवाचारी और व्यवहारिक बन सकेगी।

नई शिक्षा नीति 2025 का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य लचीली और बहुविषयक शिक्षण प्रणालियों के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। इसके अंतर्गत शैक्षणिक क्रेडिट बैंक प्रणाली के कार्यान्वयन की शुरुआत की जा रही है, जिससे छात्रों को विभिन्न संस्थानों के बीच निर्बाध रूप से स्थानांतरण की सुविधा मिल सके। यह व्यवस्था छात्रों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करेगी।

इसके साथ ही कम से कम 50 जिलों में बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जहाँ विज्ञान, कला, वाणिज्य और व्यावसायिक शिक्षा को एक साथ जोड़ा जाएगा। भारतीय शिक्षा मानकों को वैश्विक स्तर के अनुरूप बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में वृद्धि हो सके।

नई शिक्षा नीति में समावेशिता और समानता को भी विशेष महत्व दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हाशिए पर पड़े, आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा तक समान रूप से पहुंच प्राप्त हो। इसके लिए समावेशी पाठ्यक्रम और डिजिटल संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, ताकि सभी प्रकार के विद्यार्थी बिना किसी बाधा के शिक्षा ग्रहण कर सकें।

आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था भी नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही शिक्षकों को विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे शिक्षा अधिक संवेदनशील और न्यायपूर्ण बन सके।

नई शिक्षा नीति 2025 का विजन दीर्घकालिक और परिवर्तनकारी है। एनईपी 2024 से 2025 के बीच इसके कार्यान्वयन से कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर प्राप्त होने की संभावना है, जो भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे। ये उपलब्धियाँ 2030 तक की आगे की प्रगति के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेंगी। इस नीति का मुख्य फोकस समावेशिता, कौशल विकास और डिजिटल शिक्षा पर

केन्द्रित है, जिससे भारत की शिक्षा प्रणाली अधिक आधुनिक, सक्षम और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके।

2025 तक अपेक्षित उपलब्धियाँ एवं उनके प्रभाव

नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से वर्ष 2025 तक शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त होने की अपेक्षा की जा रही है। इन उपलब्धियों का उद्देश्य शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, समावेशी और रोजगारोन्मुख बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह होगी कि देश के लगभग पचास प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावहारिक व्यावसायिक अनुभव प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन से जुड़े कौशल भी प्राप्त होंगे, जिससे वे आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे और रोजगार के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकेंगे।

वर्ष 2025 तक डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता में भी व्यापक वृद्धि होने की संभावना है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री और वर्चुअल प्रयोगशालाओं का विस्तार विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जाएगा। इससे उन छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जो भौगोलिक या आर्थिक कारणों से पहले शिक्षा से वंचित रह जाते थे। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया अधिक सरल, रोचक और सुलभ बनेगी।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण में भी उल्लेखनीय सफलता मिलने की अपेक्षा है। एनईपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार शिक्षण पद्धतियों को देशभर में एकरूप किया जाएगा और लगभग अस्सी प्रतिशत शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों, तकनीक आधारित शिक्षण और विद्यार्थी-केन्द्रित पद्धतियों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि होगी और कक्षा-कक्ष में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिलेगी। कम से कम पचास जिलों में बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को लचीले और विविध विषयों में अध्ययन करने के अवसर प्राप्त होंगे। इससे छात्रों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी और शिक्षा अधिक समग्र एवं व्यावहारिक बन सकेगी।

स्कूली शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, अर्थात् जीईआर, को सौ प्रतिशत तक पहुँचाने की दिशा में भी ठोस प्रगति सुनिश्चित की जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और प्रत्येक छात्र को प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले।

इन उपलब्धियों के परिणामस्वरूप शिक्षा प्रणाली पर कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। छात्रों में शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावसायिक कौशल का भी विकास होगा, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम होगी। हाशिए पर पड़े समुदायों और दिव्यांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक व्यापक पहुँच प्राप्त होगी, जिससे शिक्षा प्रणाली अधिक समावेशी बन सकेगी।

इसके अतिरिक्त भारतीय शिक्षा मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनाया जाएगा, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर ज्ञान और नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बन सकेगा। उच्च शिक्षा में लचीले मूल्यांकन प्रणाली और कई निकास विकल्पों के कारण छात्रों पर शैक्षणिक दबाव कम होगा और वे तनावमुक्त होकर अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे। इस प्रकार वर्ष 2025 तक नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय शिक्षा

व्यवस्था में एक सकारात्मक और परिवर्तनकारी बदलाव देखने को मिलेगा।

नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

नई शिक्षा नीति को लागू करने के दौरान अनेक प्रकार की चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं, जिन्हें समझना और समय रहते समाधान करना आवश्यक है। सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा के महंगे होने की आशंका से जुड़ी हुई है। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में प्रवेश की अनुमति देने की बात कही गई है। इससे उच्च शिक्षा के अवसर तो बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही शिक्षा की लागत भी बढ़ सकती है। इसका सीधा प्रभाव निम्न और मध्यम वर्ग के छात्रों पर पड़ेगा, जिनके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो सकता है।

नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षकों की कमी भी एक गंभीर समस्या बन सकती है। नीति में कई नए सुधारों और आधुनिक शिक्षण विधियों को अपनाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन इन सुधारों को लागू करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होगी। यदि शिक्षकों को समय पर उचित प्रशिक्षण और संसाधन नहीं मिले, तो नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन हो सकता है।

शिक्षा के संस्कृतिकरण को लेकर भी कुछ राज्यों, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों, द्वारा आपत्ति जताई गई है। उनका मानना है कि त्रि-भाषा सूत्र के माध्यम से शिक्षा पर एक विशेष सांस्कृतिक प्रभाव थोपने का प्रयास किया जा रहा है। इससे भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को लेकर असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर नीति के कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है।

वित्तीय संसाधनों की कमी भी नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में एक बड़ी चुनौती है। इस नीति को पूरी तरह लागू करने के लिए कई दशकों तक निरंतर और पर्याप्त वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी। यदि केन्द्र और राज्य सरकारें शिक्षा के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध नहीं करा पाती हैं, तो नीति के कई महत्वपूर्ण लक्ष्य अधूरे रह सकते हैं।

इसके अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्र में बढ़ता व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण और निजीकरण भी एक गंभीर चिंता का विषय है। शिक्षा धीरे-धीरे सेवा के बजाय व्यापार बनती जा रही है, जिससे इसका मूल उद्देश्य कमजोर हो रहा है। निजी संस्थानों की बढ़ती भूमिका के कारण शिक्षा समानता और सामाजिक न्याय से दूर होती जा रही है।

निष्कर्ष रूप में यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक समय में नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परम्परा का समावेश अत्यंत आवश्यक है। आज की तेज़ आधुनिकता की दौड़ में व्यक्ति अपने संस्कारों, सांस्कृतिक मूल्यों और परम्पराओं को भूलता जा रहा है, जिसके कारण वह अपनी जड़ों से कटता जा रहा है। ऐसी स्थिति में नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आई है। यह नीति न केवल शिक्षा को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाती है, बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी विशेष बल देती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में रटने की प्रवृत्ति, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और अवसरों की असमानता जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। नई शिक्षा नीति इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती है और शिक्षा को संस्कार-आधारित, कौशलयुक्त और जीवनोपयोगी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस

प्रकार यह नीति नई पीढ़ी को संस्कारवान, ऊर्जावान और जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

४४४४

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2020
2. भारत सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : कार्यान्वयन दिशानिर्देश, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2021
3. यूजीसी, भारतीय ज्ञान प्रणाली पर दिशा-निर्देश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, 2022
4. कपिल कपूर, भारतीय बौद्धिक परम्परा, डी.के. प्रिंटवर्ल्ड, नई दिल्ली, 2010
5. एस. राधाकृष्णन, भारतीय दर्शन, जॉर्ज एलन एंड अनविन लिमिटेड, लंदन / भारतीय संस्करण: राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008
6. रोमिला थापर, प्राचीन भारत का इतिहास, पेंगुइन इंडिया, नई दिल्ली, 2002
7. आर.सी. मजूमदार, प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारतीय विद्या भवन, मुंबई, 1996
8. धर्मपाल, द ब्यूटीफुल ट्री: इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द एटीन्थ सेंचुरी, बिब्लिया इम्पेक्स, दिल्ली, 1983
9. अमर्त्य सेन, डेवलपमेंट ऐज फ्रीडम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1999
10. यूनेस्को, Education for Sustainable Development**, UNESCO Publishing, पेरिस, 2017
11. एनसीईआरटी, भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, 2019
12. के.एन. पनिकर, संस्कृति और शिक्षा, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2001
13. शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग), भारत में शिक्षा, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1966
14. योजना आयोग (अब नीति आयोग), शिक्षा और मानव संसाधन विकास, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2015
15. नीति आयोग, स्कूल और उच्च शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन, नीति आयोग, नई दिल्ली, 2021
16. यूजीसी, बहुविषयक शिक्षा और अकादमिक क्रेडिट बैंक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, 2021
17. अशोक मिश्रा, शिक्षा, संस्कृति और मूल्य, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014
18. अरविंद शर्मा, भारतीय धर्म और दर्शन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 2000
19. सीबीएसई, शिक्षक प्रशिक्षण और नवाचार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली, 2022
20. पी.एन. ओक, भारतीय ज्ञान परम्परा और आधुनिकता, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018